मूल्य तथा एककों की संख्याओं का वितरण नीचे दिए अनुसार है :—

राज्य	उत्पादन (1980) (करोड़ रु० में)	एककों की संख्या
कर्नाटक	199	51
महाराष्ट्र	156	222
उत्तर प्रदेश	74	34
दिल्ली	56	124
आंध्र प्रदेश	51	41
केरल	26	27

उपर्युक्त आंकड़ों में रेडियो रिसीवरों तथा कुछ अन्य ऐसे उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उत्पादों का निर्माण करने वाली यूनिटों की संख्या तथा उन के उत्पादन-मूल्य शामिल नहीं हैं जिनका संयोजन अनिवार्यतः कुटीर/दुकान स्तर पर संचालित यूनिटों द्वारा किया जाता है ।

(ग) सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Amendment of law relating to Death Penalty

617. SHRI XAVIER ARAKAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the law relating to death penalty; and

(b) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) and (b). The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1978 which was passed by the Rajya Sabha but lapsed on the dissolution of Sixth Lok Sabha sought to replace the existing session 302 IPC by a new section providing that the normal punishment for murder would be imprisonment for life and that only in certain aggravated circumstances specified therein would the court have the discretion to award death sentence. The provisions of the lapsed Bill are still under the consideration of the Government. No date can be specified at this stage as to when the legislation on the subject will be introduced in Parliament.

उत्तर प्रदेश के लिए औद्योगिक कार्यक्रम

618. **श्री उमा कान्त मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम या योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गहन औद्योगीकरण हेतु केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए बलिया, झांसी, अलमोड़ा, बस्ती, फैजाबाद, रायबरेली तथा ललितपुर जिलों का पता लगाया गया है । केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिए पता लगाए गए उत्तर प्रदेश के इन औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में अधिकतम सहायक तथा लघु उद्योगों के विकास की संभावना वाली सभी परियोजनाओं पर रिपोर्ट देने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के तीन कृतिक बलों की स्थापना कर दी गई है । इस समय कृतिक बलों का काम चल रहा है ।